SC/ST ACT, 1989

SC/ST ACT, 1989

Chp. No.	Chapter	Sections
1	PERLIMINARY प्रारंभिक	1-2
2	OFFENCES OF ATROCITIES अत्याचार के अपराध	3-9
3	CHAPTER EXTERNMENT निष्कासन	10-13
4	CHAPTER SPECIAL COURTS विशेष न्यायालय	14-15
4A	CHAPTER RIGHTS OF VICTIMS AND WITNESSES पीड़ित और साक्षी के अधिकार	15A
5	CHAPTER MISCELLANEOUS प्रकीर्ण	16-23

SC/ST ACT, 1989

OBJECT OF SC & ST ACT

Sec. 3

1. To prevent offence of Atrocity against the Members of SC/ST
SC/ST के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए

2. To provide
(i) Special Court (विशेष न्यायालय) (For Speedy Trial)
(ii) Exclusive Special Court- (अनन्य विशेष न्यायालय)[S.2 (bd)]

(For Trial of offences/ ऐसे अपराधों के विचारण के लिए

3. For relief and prohibition of victim of such offences.
ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देना और उनका पुनर्वास / Rehabilitation

4. Incidental Matter/ आनुषंगिक विषय

SC/ST ACT, 1989

CHAPTER I

Sec. 1

- Short title (संक्षिप्त नाम)
  - The Scheduled Castes and the scheduled tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- Extent (विस्तार)
  - Whole of India (संपूर्ण भारत पर)
- Commencement (प्रारम्भ)
  - 30-1-1990
  - Note
    - Date of Enactment
      - 11th Sept. 1989

Sec. 2. Definitions (परिभाषाएं)—(1)

(a) "atrocity" means an offence punishable under section 3;
अत्याचार" से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है;

Sec. 3

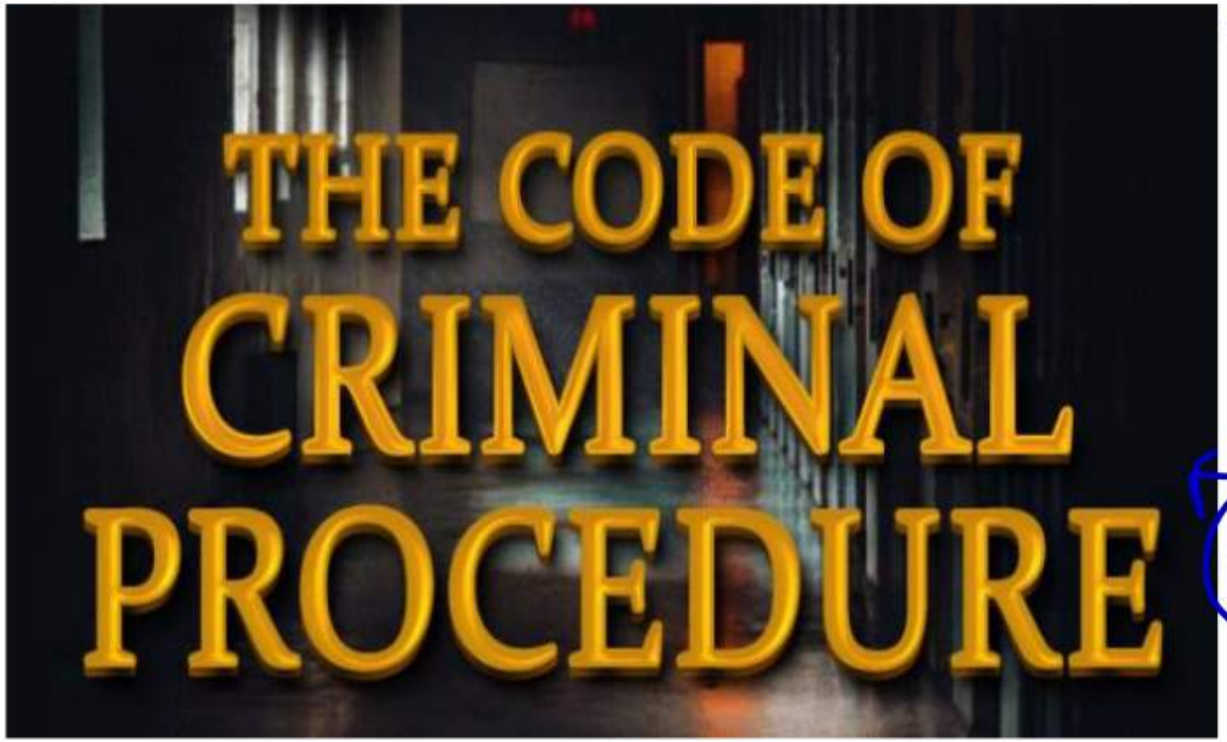

(b) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973

'संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है

CrPC

SC/ST ACT, 1989

(*bb*) "dependent" means the spouse, children, parents, brother and sister of the victim, who are dependent wholly or mainly on such victim for his support and maintenance

'आश्रित" से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहिन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिए पूर्णत: या मुख्यत: आश्रित हैं

(bc) "economic boycott" means–

"आर्थिक बहिष्कार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,

(i) a refusal to deal with, work for hire or do business with other person; or

अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने या कारबार करने से इंकार करना; या

(ii) to deny opportunities including access to services or contractual opportunities for rendering service for consideration; or

अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिनमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित हैं; या

(*iii*) to refuse to do anything on the terms on which things would be commonly done in the ordinary course of business; or

ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इंकार करना जिन पर कोई बात, कारबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतया की जाएगी; या

(*iv*) to abstain from the professional or business relations that one would maintain with other person;

ऐसे वृत्तिक या कारबार संबंधों से प्रतिविरत रहना, जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएं:

ESC

(bd) "Exclusive Special Court" means the Exclusive Special Court established under section 14(1) exclusively to try the offences under this Act

'अनन्य विशेष न्यायालय' से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 (1) के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत हैं

See. 14(1)

Sec. 2(be) "forest rights" shall have the meaning assigned to it in sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights) Act, 2006

वन अधिकार" का वह अर्थ होगा, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) में है;

Sec 3(1) → Act

(bf) "manual scavenger" shall have the meaning assigned to it in section 2 (1)(g) of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी" का वह अर्थ होगा, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2 (1) (छ) में उसका है

2(1)(g)

(bg) "public servant"

Section 21: Public Servant (लोक सेवक)- 12

- 1. Omitted
- **Army**
  - 2. Commissioned officer (आयुक्त ऑफिसर)
- **Justice**
  - 3. Judge
  - 4. Officer of Court
  - 5. Jury/ Assessor panchayat member
  - 6. Arbitrator (मध्यस्थ)
- **Criminal**
  - 7. Confining Authority
  - 8. Prevent offence
- **Civil**
  - 9. Property Doc./ Survey [on behalf of Govt.]
  - 10. Public Common Interest
  - 11. Election (निर्वाचन)
- **Other**
  - 12. On pay / service → Govt

SC/ST ACT, 1989

Sec. 2 (c) “Scheduled Castes and Scheduled Tribes”

ARTICLE 366: DEFINITION (परिभाषाएँ)

- **Clause 24** → S.C. defined
  - Article **341. Scheduled Castes** (अनुसूचित जातियां)
- **Clause 25** → S.T. defined
  - Article **342- “Scheduled Tribes”** (अनुसूचित जनजाति)

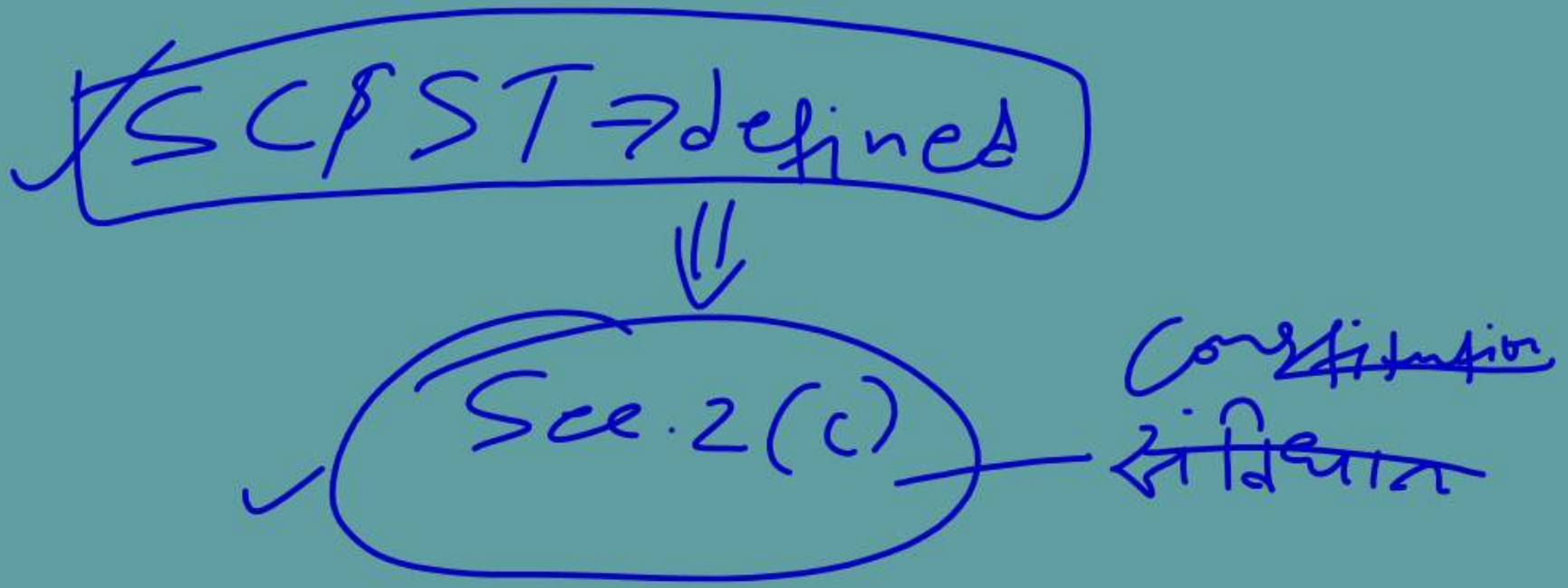
SC/ST → defined
Sec. 2(c)
Constitution
संविधान

ARTICLE 366: DEFINITION

(24) "Scheduled Castes" means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 to be Scheduled Castes for the purposes of this Constitution;

"अनुसूचित जातियों' से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है:

(25)"Scheduled Tribes" means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution;

"अनुसूचित जनजातियों" से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समदायों के भाग या उनमें के यथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है ;

366 (24) "Scheduled Castes"

341. Scheduled Castes (अनुसूचित जातियां)

(1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State or Union territory, as the case may be.

राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनसचित जातियां समझा जाएगा।

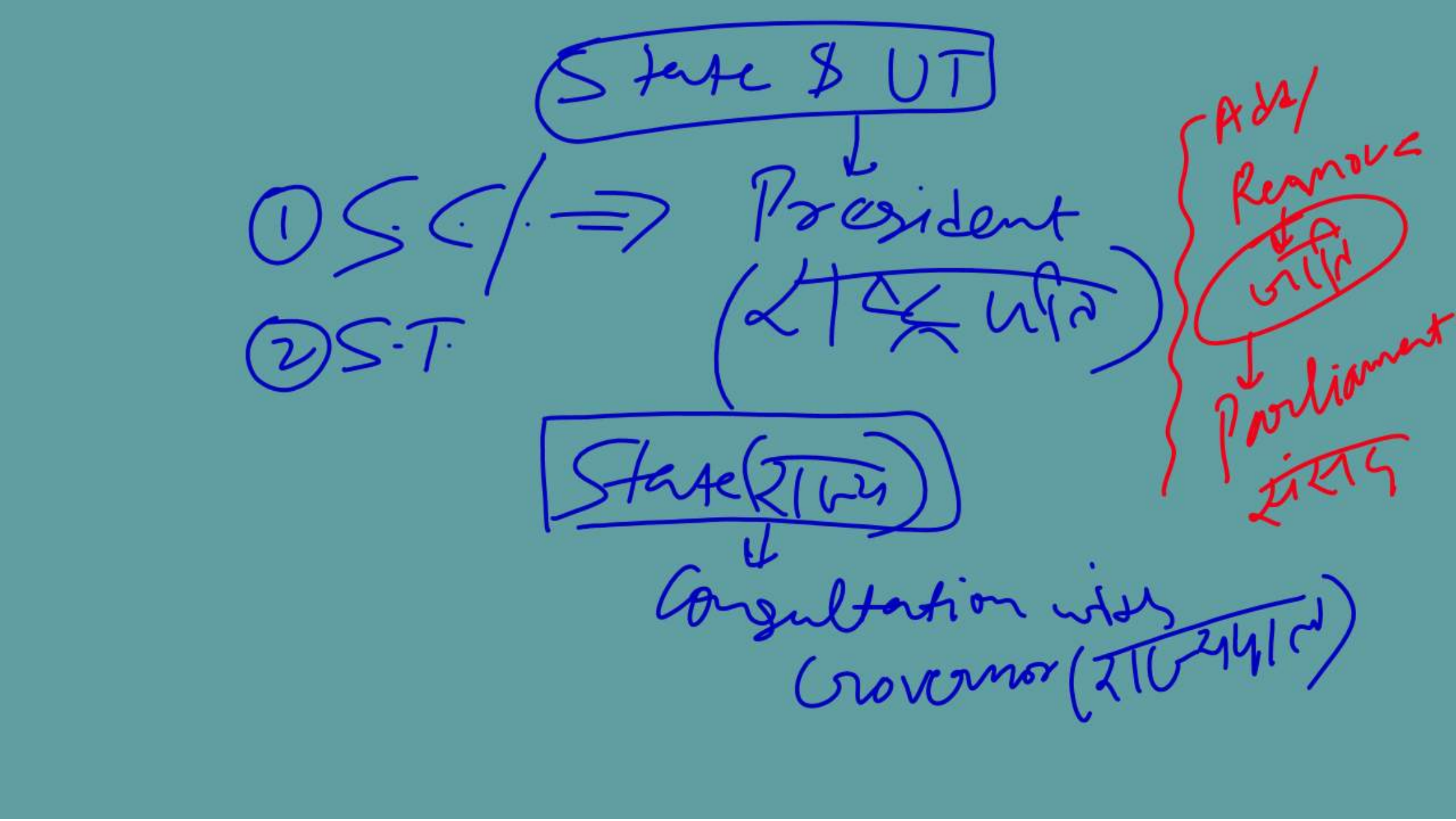

State & UT
① S.C.
② S.T.
President
(राष्ट्रपति)
State (राज्य)
Consultation with
Govornor (राज्यपाल)
Add/
Remove
Parliament
संसद

366 (24) "Scheduled Castes"

341. Scheduled Castes (अनुसूचित जातियां)

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification. संसद्, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

366 (25) "Scheduled Tribes"

↓

342- "Scheduled Tribes"

↓

(1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State or Union territory, as the case may be.

राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य [या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

366 (25) "Scheduled Tribes"

↓

342- "Scheduled Tribes"

↓

(*2*) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (*1*) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

संसद् विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियें की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

Sec. 2(d) "Special Court" means a Court of Session specified as a Special Court in section 14

S.14

"विशेष न्यायालय" से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है

SPP — Sec.15

Sec.2(e) "Special Public Prosecutor" means a Public Prosecutor specified as a Special Public Prosecutor or an advocate referred to in section 15

S.15

"विशेष लोक अभियोजक" से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है

SC/ST ACT, 1989

(*ea*) "Schedule" means the Schedule appended to this Act;

'अनुसूची" से इस अधिनियम से उपबाद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

[See section 3(2) (va)]

commits any offence specified in the Schedule shall be punishable with such punishment as specified under the Indian Penal Code

अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा

SC/ST ACT, 1989

Section under the Indian Penal Code	Name of Offence and Punishment
120A	Definition of criminal conspiracy. आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा।
120B	Punishment of criminal conspiracy. आपराधिक षड्यंत्र का दंड।
141	Unlawful assembly. विधिविरुद्ध जमाव
142	Being member of unlawful assembly. विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना।
143	Punishment for unlawful assembly. विधिविरुद्ध जमाव के लिए दंड।
144	Joining unlawful assembly armed with deadly weapon. घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना।

SC/ST ACT, 1989

145	Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse. किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना।
146	Rioting. बल्वा करना।
147	Punishment for rioting. बल्वा करने के लिए दंड।
148	Rioting, armed with deadly weapon. घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना।
217	Public servant disobeying direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture. लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा।
319	Hurt. (उपहति)
320	Grievous hurt घोर उपहति।

SC/ST ACT, 1989

323	Punishment for voluntarily causing hurt. स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड।
324	Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना।
325	Punishment for voluntarily causing grievous hurt. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दंड।
326B	Voluntarily throwing or attempting to throw acid. स्वेच्छया अम्ल फेकना या फेकने का प्रयत्न करना।
332	Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty. लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना।
341	Punishment for wrongful restraint. सदोष अवरोध के लिए दंड।
354	Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty. स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
354A	Sexual harassment and punishment for sexual harassment. लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड।
354B	Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe. विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

SC/ST ACT, 1989

354C	Voyeurism. दृश्यरतिकता
354D	Stalking. पीछा करना
359	Kidnapping. व्यपहरण
363	Punishment for kidnapping व्यपहरण के लिए दंड
365	Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person. किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण।
376B	Sexual intercourse by husband upon his wife during separation. पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन।
376C	Sexual intercourse by a person in authority. प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।
447	Punishment for criminal trespass. आपराधिक अतिचार के लिए दंड।
506	Punishment for criminal intimidation.

	आपराधिक अभित्रास के लिए दंड
509	Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman. शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।

(IPC के अनुसार दी जाएगी)

Sec. 2 (eb) "social boycott" means a refusal to permit a person to render to other person or receive from him any customary service or to abstain from social relations that one would maintain with other person or to isolate him from others;

'सामाजिक बहिष्कार' से कोई रूढिगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिये या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने के लिए, जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएं या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने के इंकार करना अभिप्रेत है; "

(ec) "victim" means any individual who falls within section 2(1)(c), and who has suffered or experienced physical, mental, psychological, emotional or monetary harm or harm to his property as a result of the commission of any offence under this Act and includes his relatives, legal guardian and legalheirs

"पीड़ित' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 2(1)(c) के परिभाषा के भीतर आता है

तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावानात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं

(ed) witness

(f) the words and expressions used but not defined in this Act

- and defined in the Indian Penal Code
- the Indian Evidence Act, 1872
- the Code of Criminal Procedure, 1973

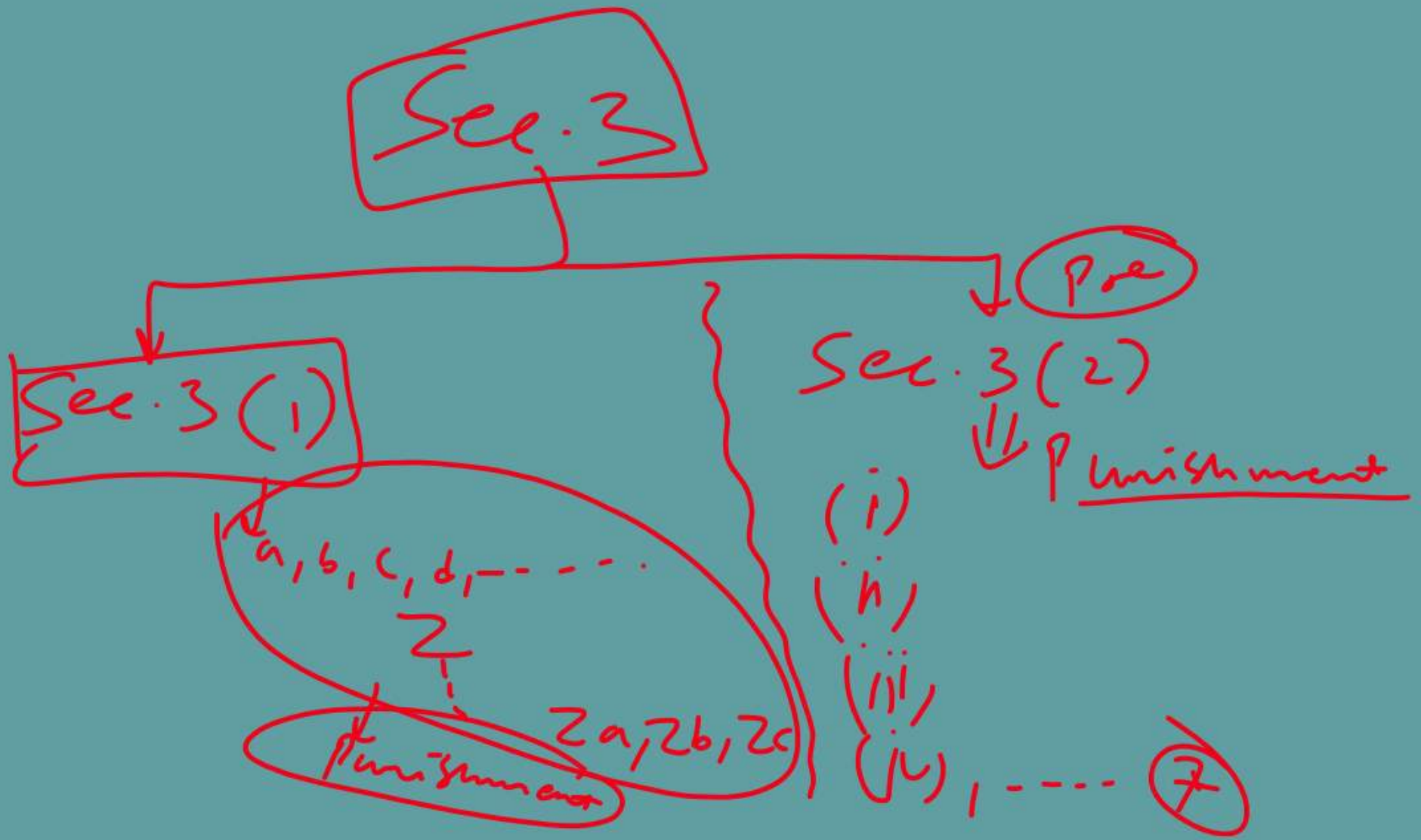

Sec. 3
Sec. 3 (1)
a, b, c, d, ...
2
2a, 2b, 2c
Punishment
Pre
Sec. 3 (2)
Punishment
(i)
(ii)
(iii)
(iv), ...
7

CHAPTER II

OFFENCES OF ATROCITIES

अत्याचार के अपराध

3. **Punishments for offences atrocities** (अत्याचार के अपराधों के लिए दंड)- [(*1*) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,—

कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

a. Inedible / Obnoxious substance into the mouth अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ मुख में रखता है

b. Dumps excreta / Sewage / Carcases / Other O.S. in premises. दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश-द्वारा पर मल-मूत्र, मल, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ

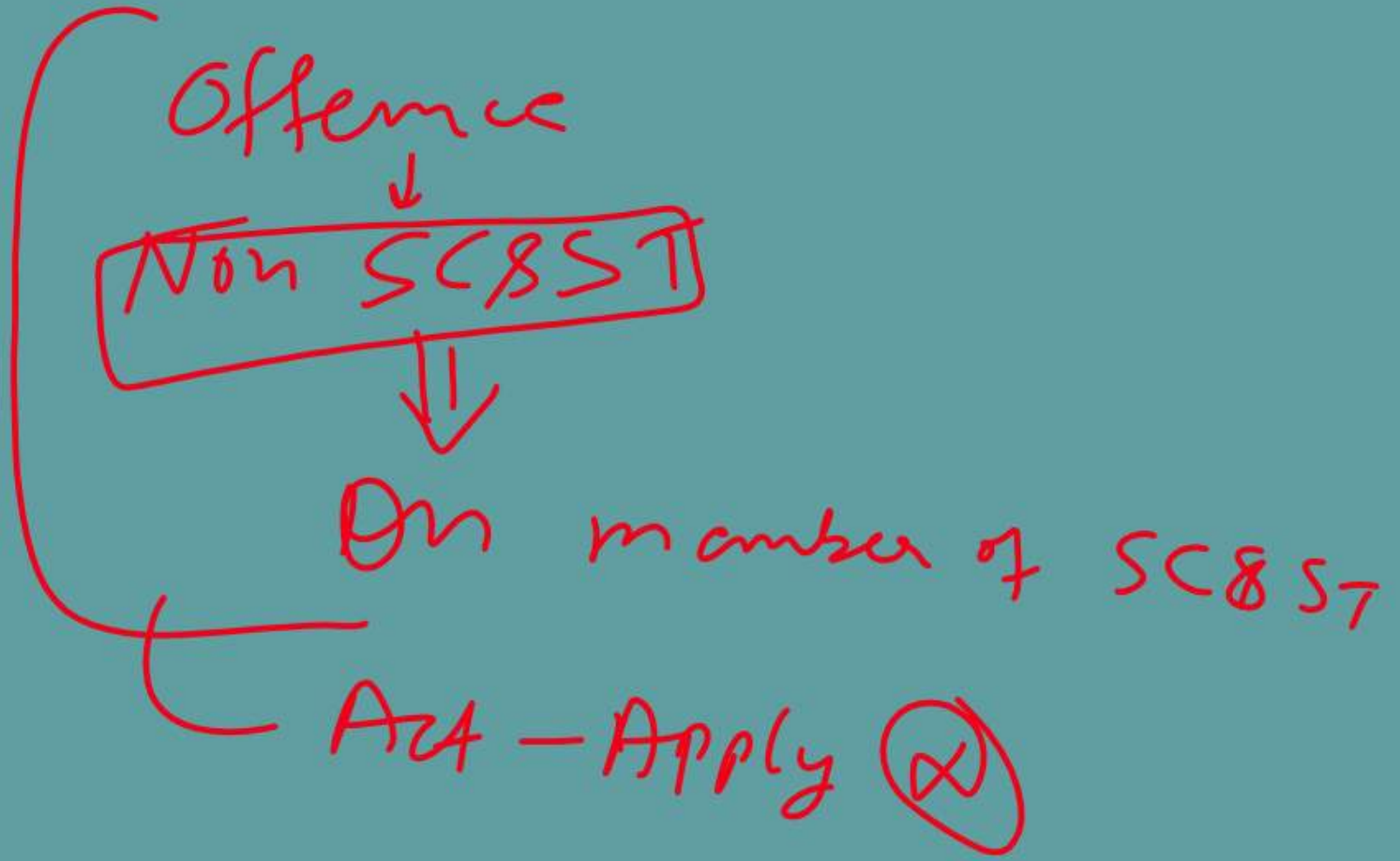
Offence
Non SC&ST
On member of SC&ST
Act - Apply

c. Injury / Insult / Annoy क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से

d. Garlands / Naked जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्ध-नग्न घुमाएगा;

e. Removing Clothes, tonsuring head removing moustaches, painting face or body
कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना

f. Wrongfully Occupies Cultivates Land.

g. Wrongfully Dispossesses/ सदोष बेकब्जा

1. land (भूमि)
2. Premises परिसर
3. Forest Right (वन अधिकारों)
4. Water जल
5. Irrigation (सिंचाई)
6. Destroy Crops फसल नष्ट

h. Begar / Other Forms of forced

i. Compels to dig graves (कब्रों को खोदने के लिये विवश)

j. Employs / permits employment to do manual Scavenging.

k. Devadasi Pratha.

l. Forces / Intimidates / Prevents

a. Not to vote / vote for a particular candidate.
मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने

b. Not to file a nomination as a candidate
नामनिर्देशन फाइल न करने

c. Not to propose / second the nomination.
नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे

m. Forces / Intimidates / Obstruct from Constitutional Post and their duties.

n. After the Poll

Causes - Hurt (उपहति) (319)

- Grevious Hurt (घोर उपहति) (320)
- Assault (हमला) (351)

o. Voted / Not having voted for a Particular Candidate किसी विशिष्ट अभ्यर्थी को मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने

p. Institutes संस्थित

false / malicious / Vexatious Suit / Criminal / Other Legal Proceeding

द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करेगा

q. Gives
False / Frivolous information to any Public Servant. किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा

r. Insults / Intimidates to humiliate अपमानित या अभित्रस्त करेगा

s. Abuses – By caste / name (within Public) Place.

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine.

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा, वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

Section 3 Clause (2)
Not Being Member of SC/ST

(i) Gives / Fabricates false evidence intending to cause / Knowing to be likely Convicted – Capital Punishment Shall be punishable

L.I. and Fine

If an innocent convicted- Non SC / ST Punished with death

SC/ST ACT, 1989

(ii) gives/ fabricates false evidence intending to cause / knowing to be Convicted for min. 7 years – (x) Capital But Punishable with 7 or upwards

Shall be Punishable with

Min. 6 Months

Max. 7 or more & Fine

SC/ST ACT, 1989

(iii) Commits / Mischief by fire / any explosive substance.
Damage any Property of SC/ST

Shall be Punished
✓ Min. 6 M.
✓ Max. 7 year
+ and fine

आग / विस्फोटक

(iv) Commits Mischief by Fire / any explosive Substance.

Destructing any building, Place of Worship / human dwelling / Custody of Prop.

↓

Shall be Punished
L.I. + Fine

आजीवन कारावास + जुर्माना

(v) Commits any Offence Under IPC with imprisonment min. 10 years

↓

L.I. + Fine

(va) Commits any offence specified in the schedule

Against a person / property

=

↓

Shall be Punishable

Same as IPC and liable to Fine

(vi) Knowingly / having reason to believe that to commit offence to Disappear the evidence with intention screening the offender

From legal Punishment

Punishable with provided Punishment for that offence

SC/ST ACT, 1989

(vii) Being a Public Servant

Commits any offence

↓

Shall be Punished

- Min. 1 Year
- Max. Actual Punished of an offence

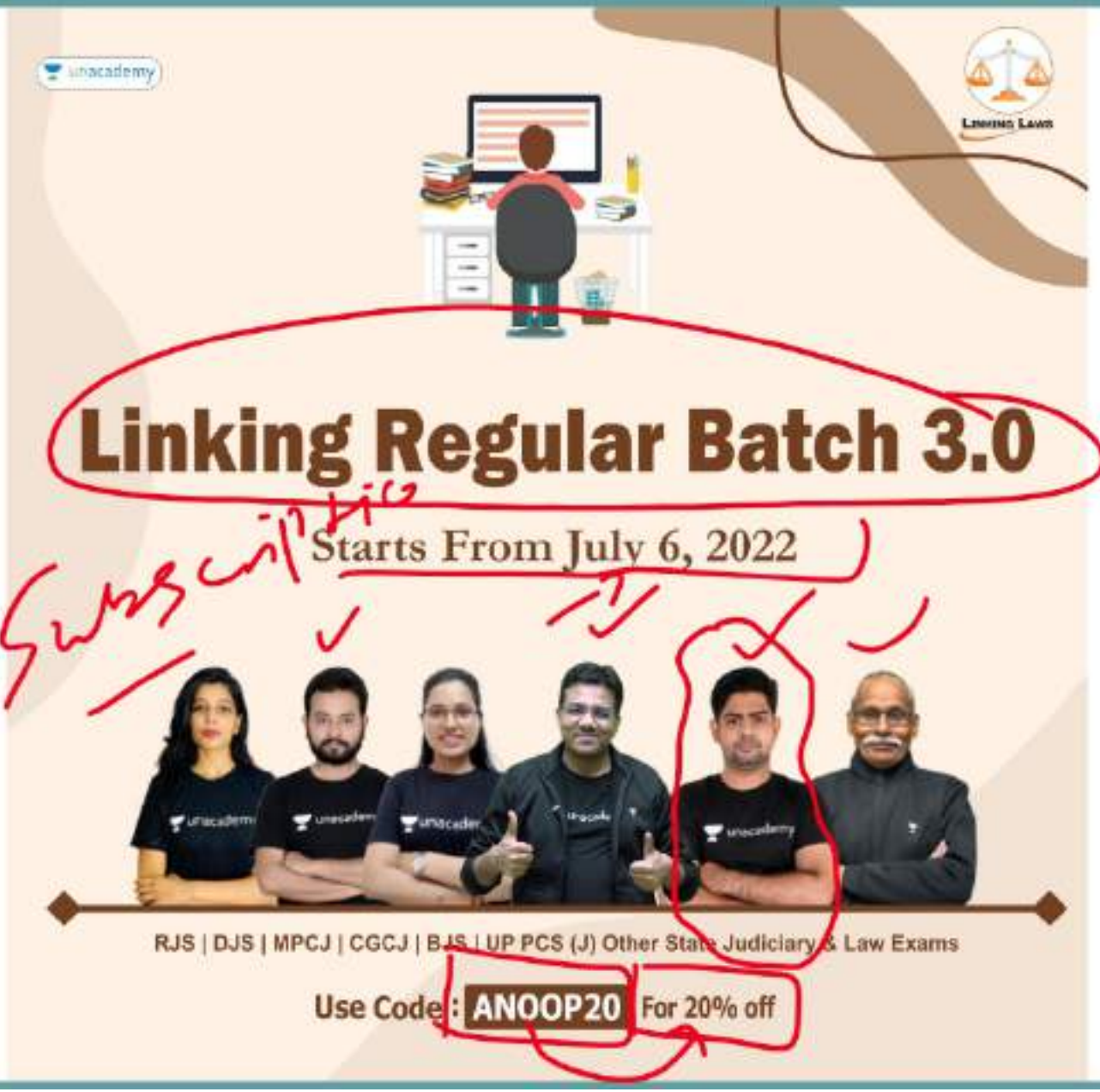

unacademy
Linking Laws
Linking Regular Batch 3.0
Starts From July 6, 2022
RJS | DJS | MPCJ | CGCJ | BJS | UP PCS (J) Other State Judiciary & Law Exams
Use Code : ANOOP20 For 20% off

GET 20% OFF ON
ALL SUBSCRIPTIONS
Offer Valid till June 30, 2022
Subscribe Now
T&C* Apply
Use Code for 20% off
ANOOP20
20% off
20

unacademy

JUDICIARY ICONIC

Now • Live

Live Doubt Solving

Get personalized one-on-one doubt solving with exam experts

1:1 Live Mentorship

Get personalized expert guidance on exam-strategy and get help whenever you are stuck

Mains focused Test series

Mains answer writing practice tests with evaluation by the experts

All benefits of PLUS

Share written answers of Subjective and Full Length Test Practice for evaluation by subject matter experts

unacademy

SPECIAL CLASS FEATURES

Interactive Live Classes

Attend Live Class, participate in Live Chat and get your doubts cleared - all during the class.

Polls for Learners

Respond to polls for a better understanding of a topic.

Raise A Hand

Plus Subscribers can Talk with educators in Live Classes and get the doubts resolve in real time.

Never Miss a Class

Get notified for lessons, upcoming courses and recommendations curated for you.

Lecture Notes

Download lecture notes and get access to recorded sessions of Live Classes. Revisit important topics whenver you need.

Anytime/ Anywhere

Watch our Live Classes anytime from anywhere from any of your device.

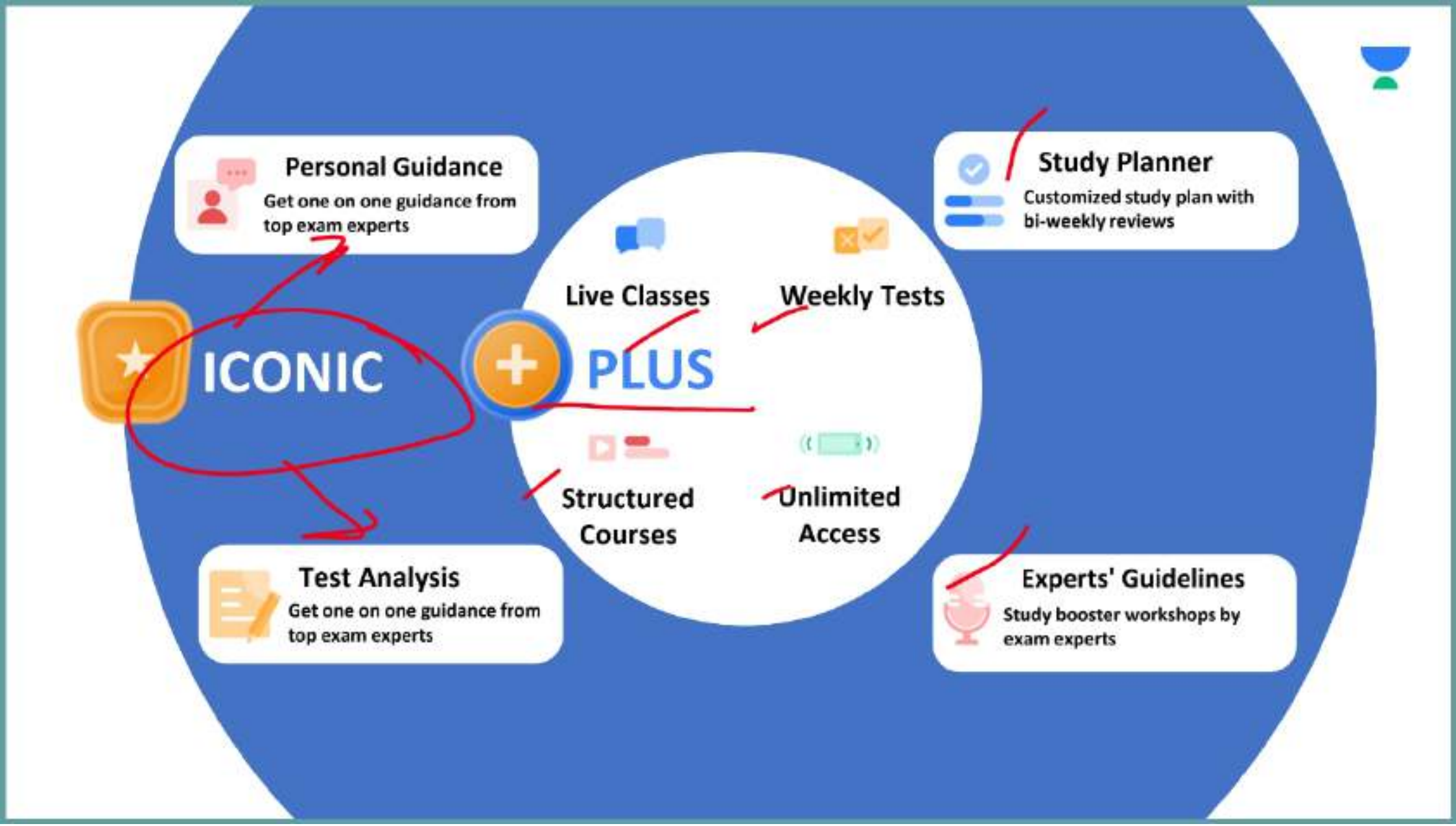
Personal Guidance
Get one on one guidance from top exam experts
Study Planner
Customized study plan with bi-weekly reviews
ICONIC
PLUS
Live Classes
Weekly Tests
Structured Courses
Unlimited Access
Test Analysis
Get one on one guidance from top exam experts
Experts' Guidelines
Study booster workshops by exam experts

Unacademy Subscription

Plus Subscription

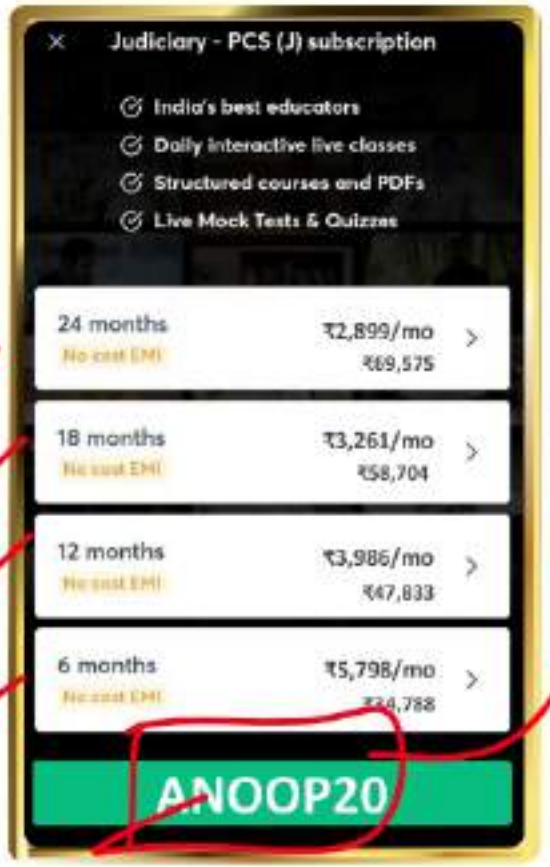

20% off

LINKING

Iconic Subscription

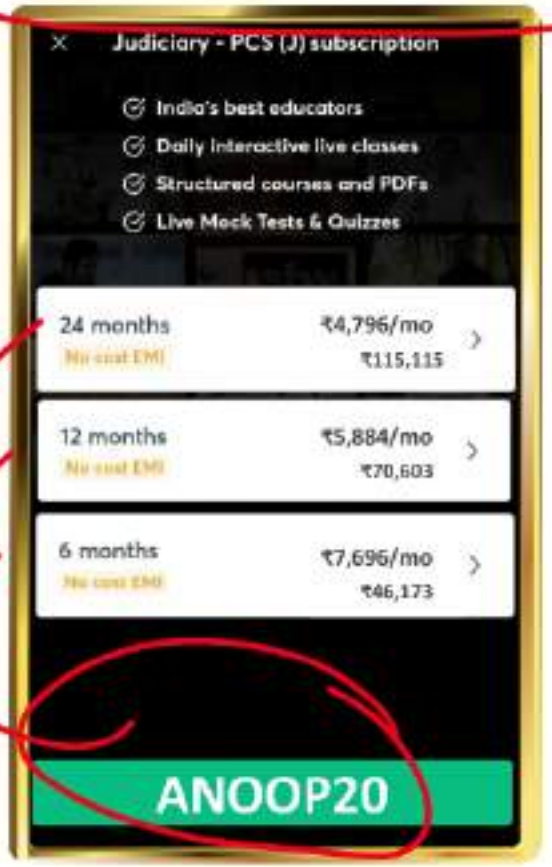

BUGS BOUNTY

Opportunity for all Learners to report any inappropriate content in the video

Be the first one to report a particular issue to claim your prize

Report any inappropriate content using the form in the description

CASE LAWS

SC/ST ACT, 1989

Case:- Kaliya Peru Mal v. State of Madras

- The most common way to commit cruelty against Scheduled Caste is to call them by their caste with the sole intention of injuring their sentiment and feeling.
  अनुसूचित जाति के खिलाफ क्रूरता करने का सबसे आम तरीका है कि उनकी भावनाओं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन्हें उनकी जाति के नाम से पुकारा जाए।

- It is rightly observed by Hon'ble Court in Kaliya Peru Mal v. State of Madras that the specific averments made in the complaint showed that the accused abused the complainant by her caste name, in filthy language, thereby causing insult and intimidation to her.
  कालिया पेरू मल बनाम मद्रास राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा यह सही देखा गया है कि शिकायत में किए गए विशिष्ट कथनों से पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को उसकी जाति के नाम से गंदी भाषा में गाली दी, जिससे उसका अपमान और धमकाया गया।

- The court held that all this amounted to an offence under Section 3 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
  अदालत ने माना कि यह सब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के तहत अपराध है।

Case:- State of Kerala v. U.P. Hassan

- In State of Kerala v. U.P. Hassan, the accused called the complainant by term "Pulaya Nadi".

केरल राज्य बनाम यू.पी. हसन, आरोपी ने शिकायतकर्ता को "पुलाया नाडी" शब्द से बुलाया। मलयालम में 'पुलायादिमोन' शब्द का अर्थ 'व्यभिचारी' या 'वेश्या का पुत्र' है।

- The word 'Pulayadimon' in Malayalam indicates meaning 'adulterer' or 'son of a prostitute'.
- The court held that this term did not have any caste implication and since accused had no motive to insult the complaint by his caste name, no offence under Section 3 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 was committed by the accused.

अदालत ने माना कि इस शब्द का कोई जातिगत निहितार्थ नहीं था और चूंकि आरोपी का अपनी जाति के नाम से शिकायत का अपमान करने का कोई मकसद नहीं था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के तहत कोई अपराध नहीं किया गया था।

Case:- Ashok Bapurao Thorat v. State of Maharashtra & Anr.

- Allegation against the accused that he had sexual intercourse with complainant belonging to the scheduled caste. The contents of FIR showing that the complainant was consenting party and there was love affair between them.

  आरोपी के खिलाफ आरोप है कि उसने अनुसूचित जाति से संबंधित शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध बनाए थे।

- The court held that complainant was not subjected to consummation because she was scheduled caste woman.

  प्राथमिकी की सामग्री से पता चलता है कि शिकायतकर्ता सहमति देने वाला पक्ष था और उनके बीच प्रेम संबंध था।

- The accused is not liable for punishment under section 3.

  अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता का परित्याग नहीं किया गया था क्योंकि वह अनुसूचित जाति की महिला थी। धारा 3 के तहत आरोपी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं है

Sec

4. Punishment for neglect of duties (कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड)—(1) Whoever, being a public servant but not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe

Punishment :- Min. 6 Month

Max. 1 Year

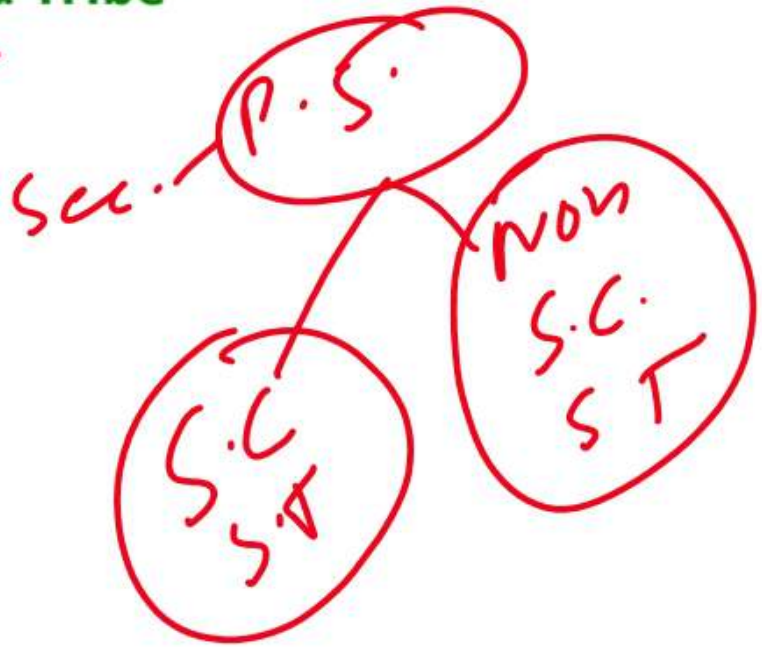

5. Enhanced punishment subsequent conviction (पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड.)—

Punishment :- Min. 1 Year

But which may extend to the punishment provided for that offence.

6. Application of certain provisions of the Indian Penal Code (भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना)—

- **Section 34, & 149**
- **Chapter III – VA**
- **Chapter XXIII**

(Chapter)
(3, 4, 5, 5A)
(23)

Case: Sec. 34- J.M. Desai Vs. State of Bombay

Acc. To S. 34—व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।
In Such Act

There is no requirement of physical presence of any person u/s 34 to commit an offence.

Sec. 34 Added by amendment Act, 1870

Barindra Kumar Ghosh Vs. Emperor

'अपराध (offence) में वे भी सहायक होते हैं जों केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं।'

यह principle 'Lord Summer' ने दिया।

Case: Mehboob Shah Vs. Emperor

Known as Sindhu River Case

This case gives difference b/w common intension and similar intention (समान आशय)

Sec. 34 is related to joint liability

Rishi Deve pandey Vs. State of U.P.

Common Intention (सामान्य आशय) घटना स्थल पर भी उत्पन्न (arise) हो सकता है।

Sec. 34 Case: Shri Kantiya Vs. State of Mumbai

Sec. 34. **Acts done by several persons in furtherance of common intention**—When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone.

सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य—जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

149. Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object—If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who, at the time of the committing of that offence, is a member of the same assembly, is guilty of that offence.

विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी- यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

7. Forfeiture of property of certain persons (कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण)—(1) The Special Court may, in addition to awarding any punishment, by order in writing, declare that any property, movable or immovable or both, belonging to the person, which has been used for the commission of that offence, shall stand forfeited to Government.

विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई सम्पत्ति, स्थावर या जंगम, या दोनों जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपहृत हो जाएगी।

8. **Presumption as to offences (अपराधों के बारे में उपधारणा)—In a prosecution for an offence under this Chapter, if it is proved that—**

इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि,

(a) the accused rendered any financial assistance in relation to the offences committed by a person accused of, or reasonably suspected of, committing, an offence under this Chapter, the Special Court shall presume that such person had abetted the offence

अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है तो विशेष न्यायालययह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है

(b) a group of persons committed an offence under this Chapter and if it is proved that the offence committed was a sequel to any existing dispute regarding land or any other matter, it shall be presumed that the offence was committed in furtherance of the common intention or in prosecution of the common object.

व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, और यदि ने यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था।

(c) the accused was having personal knowledge of the victim or his family, the Court shall presume that the accused was aware of the caste or tribal identity of the victim, unless the contrary is proved.

अभियुक्त, पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित न हो, अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजातीय पहचान का ज्ञान था।

See.

9. Conferment of powers (शक्तियों का प्रदान किया जाना)—

I (give (देना)

By state Government -> Any Officer of the S.G.

राज्य सरकार

Investigation

Ch. 5 Miscellaneous (प्रकीर्ण) [Sec. 16-23]

Sec. 16 : Power of State Govt. to impose collective fine
(राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति)

For the purpose of imposition & realization of collective fine & for other connected matters (सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे रसूल करने के प्रयोजनों के लिये और अन्य संबद्ध विषयों के लिये)

Provision of Sec. 10A of the Protection of Civil Rights Act,1955 shall apply
(सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 10क के उपबंध लागू होगें)

17. Preventive action to be taken by the law and order machinery (विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई)—

- District Magistrate जिला मजिस्ट्रेट or
- Sub-divisional Magistrate उपखंड मजिस्ट्रेट or
- Executive Magistrate कार्यपालक मजिस्ट्रेट or
- police officer not below the rank of a Deputy Superintendent of Police पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उपअधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो

may, on receiving information and after such inquiry as he may think necessary, इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो यह आवश्यक समझे

take necessary action for keeping the peace and good behaviour and maintenance of public order and tranquility and may take preventive action. शांति और सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिये आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और निवारक कार्रवाई कर सकेगा।

18. Section 438 of the Code not to apply to persons committing an offence under the Act

(अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना)

Sec. 438 of the code

Direction for grant of bail to person apprehending arrest.

(1) When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non- bailable offence,

he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section; and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail.

गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश-

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए।

See.

18A. No enquiry or approval required (किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना)—(1) For the purposes of this Act,—

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,

(a) preliminary enquiry shall not be required for registration of a First Information Report against any person; or

किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; या

(b) the investigating officer shall not require approval for the arrest

किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि आवश्यक हो, से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी

(2) The provisions of section 438 of the Code shall not apply to a case under this Act, notwithstanding any judgment or order or direction of any Court.

किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे।

438 of CrPC

19. Section 360 of the Code or the provisions of the Probation of Offenders Act not to apply to persons guilty of an offence under the Act (इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबन्ध का लागू न होना)—

to any person above the age of eighteen years who is found guilty of having committed an offence under this Act.

अठारह वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है

20. Act to override other laws

(अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना)

21. Duty of Government to ensure effective implementation of the Act (अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य)—

(1) Subject to such rules as the Central Government may make in this behalf, the State Government shall take such measures as may be necessary for the effective implementation of this Act.

राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हों।

22. Protection of action taken in good faith (सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण)—

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or against the State Government or any officer or authority of Government or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

23. Power to make rules (नियम बनाने की शक्ति)—

The Central Government

Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session

for a total period of thirty days

लोक सभा — राज्य सभा

CASE LAWS

Case:- Shayam Singh alias Dhannu and Another v. State of M.P.

- The accused allegedly called the complainant by caste name (Chamar in this case).
- The court held that there was no offence because taking the name of caste of any citizen of this country itself is not the offence till it is not taken with the intention to humiliate that person because of his community.

आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को जाति के नाम से बुलाया (इस मामले में चमार) अदालत ने माना कि कोई अपराध नहीं है क्योंकि इस देश के किसी भी नागरिक की जाति का नाम लेना तब तक अपराध नहीं है जब तक कि उस व्यक्ति को उसके समुदाय के कारण अपमानित करने के इरादे से नहीं लिया जाता है।

Case:- Karan Singh v. State of Haryana

In Karan Singh v. State of Haryana, complainant and her companion were molested as they were women.

कर्ण सिंह बनाम हरियाणा राज्य में, शिकायतकर्ता और उसके साथी के साथ छेड़छाड़ की गई क्योंकि वे महिलाएं थीं।

The court held that as such women were not molested because of the fact that they belonged to Scheduled Caste, hence, accused could not be prosecuted for atrocities on Scheduled Caste woman under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989.

अदालत ने माना कि चूंकि ऐसी महिलाओं के साथ इस तथ्य के कारण छेड़छाड़ नहीं की गई थी कि वे अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जाति की महिला पर अत्याचार के लिए आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

Caste clashes

Dalits were at the receiving end of almost all these atrocities like

दलितों को लगभग इन सभी अत्याचारों का शिकार होना पड़ा

- **Khairlanji massacre in Maharashtra 2008**
  महाराष्ट्र 2008 में खैरलांजी हत्याकांड

- **Bhima-Koregaon violence in Maharashtra 2017**
  महाराष्ट्र 2017 में भीमा-कोरेगांव हिंसा

- **Una violence**
  ऊना हिंसा

44 Dalit — wages

01. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 कब लागू हुआ?

(a) 1 जनवरी 1990
(b) 30 जनवरी 1990
(c) 11 सितम्बर 1989
(d) 12 सितम्बर 1989

01. When did the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 come into force?

(a) 1 January 1990
(b) 30 January 1990
(c) 11 September 1989
(d) 12 September 1989

02. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है?

Under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, which section provides for the provision ofaspecial court?

(a) 14
(b) 17
(c) 21 (1)
(d) 21 (3)

03. विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम, 1989 के कौन सी धारा में दिया गया है?

In which section of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, the provision of Special Public Prosecutor is given?

(a) धारा 15
(b) धारा 12
(c) धारा 14
(d) धारा 13

04. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत लोक व्यवस्था और शान्ति बनाये रखने तथा अत्याचारग्रस्त घोषित क्षेत्रों में अत्याचार रोकने के लिये कौन उत्तरदायी है?

(a) जिला मजिस्ट्रेट
(b) उप-खण्ड मजिस्ट्रेट
(c) पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप-अधीक्षक के पद से नीचे कानहो
(d) उपर्युक्त सभी

04. Under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, who is responsible for maintaining public order and peace and preventing atrocities in the areas declared atrocities?

(a) District Magistrate
(b) Sub-Divisional Magistrate
(c) Police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police
(d) All of the above

DSP

05. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय कौन गठित करता है?

(a) अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा
(b) केन्द्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से
(c) राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से
(d) राज्यपाल द्वारा सत्र न्यायालय को विशेष दर्जा देकर

05. Who constitutes the Special Court under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

(a) By the Central Government through notification
(b) By the Central Government in consultation with the Chief Justice of India
(c) By the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of the State
(d) By giving special status to the Court of Session by the Governor

06. किस मामला (Case) में अधिनियम की धारा 18 की संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर विचार किया गया?

(a) मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकृष्ण बलौटिया
(b) करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य
(c) अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
(d) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम डॉ० दीनानाथ शुक्ला

In which of the following cases the question of the constitutional validity of section 18 of the Act was considered?

(a) State of Madhya Pradesh Vs. Ramkrishna Baloutia → H.W.
(b) Kartar Singh Vs. State of Punjab
(c) Ashok Kumar Gupta Vs. State of Uttar Pradesh
(d) State of Uttar Pradesh vs. Dr. Dinanath Shukla

07. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत किए गए अपराधों के लिए जाँच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सोंपेगा?

In how many days will the Inquiry Officer submit his report for the offenses committed under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

(a) 15
(b) 20
(c) 25
(d) 30 days

A. 17

Abolition of Untouchability

08. किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक, सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?

Under which article fundamental, socio-economic, political, and cultural rights have been provided to Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

(a) अनुच्छेद 20 / Article-20
(b) अनुच्छेद 19 19
(c) अनुच्छेद 18 18
(d) अनुच्छेद 17 17

09. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के विचारण की अधिकारिता किसको है?

Who has the jurisdiction to try the offenses punishable under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

(a) विशेष न्यायालय
(b) जिला मजिस्ट्रेट
(c) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(d) मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग

Special Court
D.M.
C.J.M
JM-Ist Class

10. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत किन न्यायालयों को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया जाता है?

(a) सत्र न्यायालय
(b) न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय
(c) जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय
(d) जिला जज के न्यायालय

10. Which courts are designated as special courts under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act?

(a) Court of Session
(b) Court of Judicial Magistrate
(c) District Magistrate's Court
(d) District Judge's Court

11. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की किस धारा के तहत आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है?

(a) धारा2(बी)
(b) धारा2(बीसी)
(c) धारा 2(बीएफ)
(d) धारा2(बीजी)

11. Economic boycott is defined under which section of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

(a) Section2(B)
(b) Section2(BC)
(c) Section2(BF)
(d) Section2(BG)

12. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी

(a) 11.3.1989
(b) 11.6.1989
(c) 11.9.1989
(d) 11.12.1989

12. When was the President's assent to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 received?

(a) 11.3.1989
(b) 11.6.1989
(c) 11.9.1989
(d) 11.12.1989

13. 'क' ने अपने अनुसूचित जाति के नौकर को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये आदेशित किया। कोई सबूत इस बात का नहीं है कि 'क' ने नौकर को इरादतन अपमानित किया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 क्या इस मामले में लागू होता है

(a) हां
(b) नहीं
(c) नोकर की इच्छा पर निर्भर है।
(d) धारा3(1) (x) लागू होती है।

'A' ordered his Scheduled Caste servant using caste-indicative words. There is no evidence that A will fully insulted the servant. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is applicable in this case

(a) Yes
(b) No
(c) Depends on the will of the servant
(d) Section 3(1)(x) applies

14. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कितनी धाराएँ हैं?

(a) 18
(b) 22
(c) 23
(d) 27

14. How many sections are there under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

(a) 18
(b) 22
(c) 23
(d) 27

23 Sec Ch-5 SH-1

Linking Laws Anoop Sir